चलो, कि मंजिल दूर है

सामयिक

प्रभात कुमार राय

अन्ना हजारे ने आखिरकार 13 दिनों तक जारी राष्ट्रव्यापी जन उभार से परिपूर्ण जद्दोजहद के पश्चात अपने अनशन का पटाक्षेप अंजाम दिया। अन्ना हजारे ने साफ तौर पर कहा कि जन-लोकपाल विधेयक के ज्वलंत प्रश्न पर भारतीय जनगण को अभी तो आधी-अधूरी फतह हासिल हुई, संपूर्ण विजयश्री तो तब मिलेगी, जब जन-लोकपाल विधेयक को संसद पारित कर देगी। उनका संघर्ष वस्तुतः व्यवस्था परिवर्तन के लिए है, जन-लोकपाल बिल तो उस दिशा में महज एक कदम है। अभी तो लड़ाई का आगाज हुआ है। संवैधानिक मकसदों को हासिल करने के खातिर अमीर-गरीब के मध्य उत्पन्न भयावह आर्थिक फर्क को खत्म करना होगा। सत्ता के विकेंद्रीकरण द्वारा ग्राम सभाओं को ताकत प्रदान करनी होगी। चुनाव प्रक्रिया में प्रबल सुधार अंजाम देने होंगे, इत्यादि। अन्ना आंदोलन से तशकील हुई संपूर्ण परिस्थिति में फैज अहमद फैज की नज्म के चंद हिस्से जेहन में अनायास हिलोरे लेने लगे-

ये दाग-दाग उजाला ये शब गुजीदा सहर
वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं
ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर
चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं
अभी गिरानी ए शब में कमी नहीं आई
नजाते दीदा ओ दिल की घडी नहीं आई
चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई

हुकूमत को आखिरकार अन्ना आंदोलन में भारतीय जनगण के समक्ष नतमस्तक होने के लिए विवश होना पड़ा। सरकार ने अन्ना आंदोलन को कुचलने की प्रत्येक कोशिश की। कांग्रेसी प्रवक्ताओं ने अन्ना को सिर से पांव तक भ्रष्ट और सेना का भगौड़ा करार देने की तक कुचेष्टा की। कांग्रेस नेतृत्व की बौखलाहट में तो इस कदर इजाफा हुआ कि उसने अन्ना आंदोलन को मीडिया का ही सृजन करार दे दिया। मीडिया पर कांग्रेस नेतृत्व द्वारा की गई इस बेहूदा टिप्पणी को केवल बौखलाहट करार दिया गया। कांग्रेस नेतृत्व इस तथ्य को समझने में नाकाम रहा कि 2004 से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के साथ मजबूती से जुड़े रहे, मध्यम वर्ग ने अब कांग्रेस का परित्याग कर दिया है। आबादी के तकरीबन 25 प्रतिशत तक पहुंच चुका मध्यवर्ग, विगत पंद्रह वर्षो में एक अत्यंत शक्तिशाली वर्ग के तौर पर उभरा। 1991 से आर्थिक सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लाइसेंस राज की जकड़न से बाहर निकाला। एक विशाल प्राइवेट सैक्टर की आधार शिला पर ताकतवर मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ। भारतीय मीडिया ने भी बड़े पैमाने पर टेलीविजन की रंगीन दुनिया में कदम रखा। शासकीय दूरदर्शन की दुनिया से निकल कर प्राईवेट चैनल्स ने छोटे शहरों और कस्बों के साथ ही लाखों गांवों तक अपनी पहुंच कायम की। क्षेत्रीय अखबारों ने तो स्वयं को विस्तारित करने में अनोखा कमाल कर दिखाया। मीडिया की प्रखर पांतों में मध्यम वर्गीय युवा चेहरों ने अपनी जोरदार पहचान स्थापित की। मध्यवर्ग के अत्यंत प्रतिभाशाली नौजवानों की पहली पसंद अब प्राइवेट सैक्टर की नौकरियां बन गईं।

मुख्य विपक्षी राजनीतिक दल भाजपा ने अत्यंत मौकापरस्त राजनीति का परिचय दिया। जन-लोकपाल बिल पर राष्ट्रव्यापी जन लहर का दीदार करने के पश्चात ही शासकीय भ्रष्टाचार को कर्नाटक में पालने-पोसने वाली भाजपा ने बड़े ही नाज नखरों और मान मुनव्वल के बाद संसद में जन-लोकपाल बिल पर अपना समर्थन दिया है।

विगत कुछ वर्षों में शासकीय भ्रष्टाचार के कई बड़े मामले प्रकाश में आए, जिसके कारणवश सचेत-शिक्षित मध्यम वर्ग बेहद आहत हुआ। मूलतः मध्यवर्गीय चरित्र के मीडियाकर्मी भी राजकोष की जबरदस्त लूट से अत्यंत आहत और अधीर हुए। ऐसे विकट दौर में अन्ना हजारे ने जब जंतर-मंतर पर आजादी के दौर की भ्रष्टतम सरकार को ललकारा और सरकारी भ्रष्टाचार पर कड़ी लगाम कसने के लिए जन-लोकपाल विधेयक का मजमून पेश किया तो जैसे समस्त मध्यवर्ग के साथ ही साथ भारत का मीडिया भी रातोरात अन्ना हजारे का दिवाना हो उठा। अरबों-खरबों की धनराशि की अकूत भ्रष्टाचारी लूट को संरक्षण प्रदान करने वाला कांग्रेस नेतृत्व कदाचित मध्यवर्ग के गुस्से को समझने में नाकाम रहा। राजनीतिक पैंतरेबाजी खेलते हुए लोकपाल बिल पर ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, जिसमें अन्ना हजारे के आग्रह के बावजूद विपक्षी दलों को बाहर रखा गया। आखिरकार हुकूमत ने अत्यंत लचर नाकारा लोकपाल बिल संसद के पटल पर पेश कर दिया। इस तमाम राजनीतिक छल-कपट के बावजूद कांग्रेस क्या यह उम्मीद रखती है कि मध्यवर्गीय नैतिकता के कुछ बचे खुचे संस्कारों से ओतप्रोत भारतीय मीडिया कांग्रेस लीडरशिप की कूटनीति के कसीदे पढ़ता?

कांग्रेस नेतृत्व के साथ ही साथ मुख्य विपक्षी राजनीतिक दल भाजपा ने भी जन-लोकपाल बिल के प्रश्न पर अत्यंत मौकापरस्त राजनीति का परिचय पेश किया। जन-लोकपाल बिल पर जबरदस्त राष्ट्रव्यापी जन लहर का दीदार करने के पश्चात ही शासकीय भ्रष्टता को कर्नाटक प्रांत में दीर्घकाल तक पालने पोसने वाली भाजापा ने बड़े ही नाज नखरों और मान मुनव्वल के बाद संसद में जन-लोकपाल बिल पर अपना समर्थन प्रदान करने का फैसला लिया, ताकि वह सरकार विरोधी जन-लहर का राजनीतिक फायदा उठा सके। कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भाजापा के जन-लोकपाल बिल के प्रश्न पर कुटिल राजनीतिक आचरण को मद्देनजर रखते हुए, एक तथ्य स्पष्ट तौर पर उभर राष्ट्र के समक्ष आता है कि राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति कितने गहरे रसातल में जा चुकी है, जहां से उबार कर पुनः राजनीतिक जन-संस्कृति का नैतिक पुनर्निर्माण करना अत्यंत दुष्कर कार्य सिद्ध होगा। राष्ट्र निर्माण के कठिन नैतिक कार्य में मीडिया को राजसत्ता के चौथे स्तंभ के रूप में एक शानदार भूमिका का निर्वाह करना होगा। सुप्रीमकोर्ट ने राजसत्ता के अहम स्तंभ के तौर पर शक्तिशाली भ्रष्ट राजनेताओं को जेल की सलाखों के पीछे धकेल कर एक नया इतिहास रच डालने का आगाज कर दिया। अन्ना आंदोलन की सक्रिय पांतों में करोड़ो किसानों और मजदूरों की शिरकत के बिना व्यवस्था परिवर्तन का चिरंजीवी स्वप्न कदाचित साकार नहीं हो सकेगा, जो जंगे-ए-आजादी के क्रांतिकारी योद्धाओं द्वारा देखा गया। घृणित सांप्रदायिकता, अमानवीय जातिवाद और घनघोर आर्थिक-सामाजिक विषमता को भारतीय समाज में पूर्णतः नेस्तानाबूद किए बिना, यह कतई मुमकिन नहीं कि भारतीय संविधान में घोषित लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।

(लेखक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं)

Reproduced by www.hobbyshobby.com with author's permission